

## **NHRC urges states to end manual waste cleaning**

NHRC, India, in a letter to all the Chief Secretaries and Administrators of States and Union Territories, asked to ensure the immediate implementation of the 14 directives issued by the Supreme Court in its landmark 2023 judgment (Dr Balram Singh v/s Union of India, 2023 INSC 950), aimed at eradicating the inhuman and caste-based practice of manual scavenging and hazardous sewer cleaning. The Commission noted that the practice constitutes a grave violation of human rights, especially the right to life with dignity and equality.

## No toilets in Bhadrak schools NHRC asks SME Secy to submit ATR

PNS ■ Baleswar

The National Human Rights Commission (NHRC) has directed the Secretary, School and Mass Education Department, Odisha, to submit an action taken report (ATR) on the facts as mentioned in the report of the District Magistrate, Bhadrak and District Education Officer (DEO), Bhadrak on the issue of lack of toilets in primary schools situated in the district headquarters.

Considering the petition filed by activist-lawyer Radhakanta Tripathy and the reply submitted by the district Collector and the DEO, the NHRC passed the order.

Tripathy in his petition submitted that due to lack of toilets, the students of Elkha Project Upper Primary

School, Apartibindha, Mirzapur UGME school, and the Government Upper Primary School, Patanasahi, of Bhadrak district were suffering a lot. He had submitted that India's first bio-toilets were established in Bhadrak district but due to apathy of the administration and failure of the concerned authorities, the same could not be sustained.

The NHRC sought a reply from the authorities within six weeks. A copy of the order also has been marked to the Chief Secretary for information.

The NHRC referred to the JK Raju vs State of Andhra Pradesh in which the Supreme Court ruled that separate toilets for boys and girls, as well as drinking water facilities, are integral to the Right to Education (RTE).

## Class 12 student sexually abused at JNV: NHRC seeks ATR

**STATESMAN NEWS SERVICE**

BHUBANESWAR, 16 MAY:

The alleged sexual assault of a 17-year-old boy, a Class XII student of Centre-run Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) in Mundali in Cuttack district has come under NHRC's scanner with the top rights panel asking the Cuttack rural SP to submit an Action Taken Report (ATR) within two weeks.

The rights panel acting on a petition filed by human rights lawyer Radhakanta Tripathy, passed the order on Thursday.

A minor boy (aged 17 years)

a Class XII student, at Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV), Mundali has been sexually assaulted by a labourer hired for painting work. The incident occurred when the victim was assaulted in the boys' hostel toilet. The labourer allegedly locked the gate and committed the assault. The victim informed his parents, who filed an FIR at Baranga Police Station on 11 April last, the petition noted.

The NHRC said it was a serious matter and directed the SP to report expeditiously within a period of 15 days treating the matter as urgent.

## मंत्री विजय शाह के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत

बूंदी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में शामिल महिला सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह की आपत्तिजनक टिप्पणी सामने आई थी। इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केस दर्ज कर लिया है। आयोग ने यह कार्रवाई राजस्थान बीज निगम के पूर्व निदेशक बूंदी निवासी चर्मेस

शर्मा की शिकायत पर की है। शर्मा ने आयोग में मेल के जरिए ऑनलाइन शिकायत दी थी। आयोग ने इस पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। शिकायत में कहा गया है कि विजय शाह की टिप्पणी भारतीय नारी सम्मान की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली है। यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता के भी खिलाफ है। शिकायत में मांग की गई है कि भारतीय सेना की सभी महिला अधिकारियों के सम्मान की रक्षा की जाए।

## मंत्री विजय शाह के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत

बूंदी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में शामिल महिला सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह की आपत्तिजनक टिप्पणी सामने आई थी। इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केस दर्ज कर लिया है। आयोग ने यह कार्रवाई राजस्थान बीज निगम के पूर्व निदेशक बूंदी निवासी चमेश शर्मा की शिकायत पर की है। शर्मा ने आयोग में मेल के जरिए ऑनलाइन शिकायत दी थी। आयोग ने इस पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

ETV Bharat

## **NHRC Registers Case Against MP Minister Vijay Shah For Comments On Col Sofiya Qureshi**

Congress leader Charmesh Sharma of Bundi had brought the matter to the notice of the apex human rights body on Thursday.

<https://www.etvbharat.com/en/!state/mp-minister-vijay-shah-controversial-remark-on-colonel-sophia-qureshi-nhrc-filed-a-case-enn25051606892>

By ETV Bharat English Team | Published : May 16, 2025 at 10:07 PM IST

1 Min Read

Bundi: The National Human Rights Commission (NHRC) has registered a case against Madhya Pradesh Minister Vijay Shah over his controversial remarks Indian Army's Colonel Sofiya Qureshi.

Congress leader Charmesh Sharma of Bundi had brought the matter to the notice of the apex human rights body on Thursday. Sharma described Shah's objectionable remarks on Colonel Qureshi as hurting the dignity of Indian women's honor and against national unity and integrity.

Sharma, the former director of Rajasthan Seed Corporation has urged NHRC to take appropriate action against Shah. He said respect of Indian Army is paramount. "Such insult of any military officer cannot be tolerated. It is even more shameful that such derogatory remarks were made on a woman officer of the Indian Army by a person who has taken oath of the Constitution and is holding the post of a minister of a state government," Sharma said.

Earlier, the Supreme Court sharply rebuked Shah over his controversial remarks directed at Colonel Qureshi. The Chief Justice of India, BR Gavai, described the minister's comments as unacceptable and insensitive, stating that individuals occupying constitutional positions should exercise restraint in speech.

Chief Justice Gavai questioned the conduct of Mr Shah by asking, "What sort of comments are you making? You should show some sense of sensibility. Go and apologise in High Court." The remarks, which have drawn widespread criticism from the Opposition, military veterans, and even some members of the ruling Bharatiya Janata Party (BJP), also led to an FIR against the minister.

Navbharat Times

## कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी को लेकर बुरे फंसे मंत्री विजय शाह, अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करेगा जांच

<https://navbharattimes.indiatimes.com/state/rajasthan/bundi/human-rights-commission-investigates-minister-vijay-shah-for-controversial-remarks-on-colonel-sofia-ghureshi/articleshow/121216904.cms>

Authored by: पुलकित सक्सेना•Contributed by: अर्जुन अरविंद|Lipi•16 May 2025, 9:33 pm

मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी से विवाद हुआ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में केस दर्ज किया है। बूंदी के कांग्रेस नेता चर्मेश शर्मा ने आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को नारी सम्मान के खिलाफ बताया गया है।

बूंदी: महिला सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केस दर्ज कर लिया है। आयोग ने बूंदी के कांग्रेस नेता राजस्थान बीज निगम के पूर्व निदेशक चर्मेश शर्मा की शिकायत पर शुक्रवार को केस दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के एक्शन में आने के बाद मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ती जा रही है।

आयोग ने शुक्रवार को दर्ज किया केस

इस मामले में बूंदी के चर्मेश शर्मा ने गुरुवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत की थी। जिस पर आयोग ने शुक्रवार को इस मामले में केस दर्ज कर लिया। मानवाधिकार आयोग में दर्ज शिकायत में बूंदी के कांग्रेस नेता चर्मेश शर्मा ने पहलगाम हमले के बाद भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी के विरुद्ध मध्यप्रदेश के सरकार के मंत्री विजय शाह द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी को भारतीय नारी सम्मान की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला व राष्ट्रीय एकता व अखंडता की विरुद्ध बताया गया है।

कड़ी कार्यवाही की मांग

शिकायत में मानव अधिकार आयोग से भारतीय सेना की सभी महिला अधिकारियों की नारी सम्मान की गरिमा सुनिश्चित करने के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी के विरुद्ध आपत्तिजनक बयान देने वाले मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की मांग की गई।

भारतीय सेना का सम्मान सर्वोपरि - शर्मा

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में विजय शाह के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाने वाले बूंदी के कांग्रेस नेता राजस्थान बीज निगम के पूर्व निदेशक चर्मेश शर्मा ने कहा कि भारतीय सेना का सम्मान सर्वोपरि है। किसी भी सैन्य अधिकारी का इस तरह से अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।

यह और भी शर्मनाक है कि जिस व्यक्ति ने संविधान की शपथ लेकर एक राज्य सरकार के मंत्री का पद ग्रहण कर रखा है उसके द्वारा ऐसी अपमानजनक टिप्पणी भारतीय सेना की महिला अधिकारी के विरुद्ध की गयी है। प्रत्येक देशवासी को वर्तमान समय में भारतीय सेना का हर स्तर पर हर हौसला बढ़ाना चाहिये।



Amar Ujala

## Rajasthan News: एमपी के मंत्री शाह पर मानवाधिकार आयोग का एक्शन, बूंदी के कांग्रेस नेता की शिकायत पर मामला दर्ज

<https://www.amarujala.com/rajasthan/bundi/rajasthan-news-human-rights-commission-filed-a-case-against-minister-vijay-shah-in-colonel-sophia-case-2025-05-16>

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बूंदी Published by: अर्पित याज्ञनिक Updated Fri, 16 May 2025 07:46 PM IST

सार

बूंदी

राजस्थान बीज निगम के पूर्व निदेशक और बूंदी के कांग्रेस नेता चर्मेश शर्मा की शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने शुक्रवार को केस दर्ज कर लिया। शिकायत में मंत्री के बयान को भारतीय नारी सम्मान और राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध बताया गया है।

विस्तार

पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई में शामिल सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब बूंदी के कांग्रेस नेता राजस्थान बीज निगम के पूर्व निदेशक चर्मेश शर्मा की शिकायत पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के एक्शन में आने के बाद शुक्रवार को केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी।

आयोग ने शुक्रवार को दर्ज किया केस

मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी के विरुद्ध आपत्तिजनक बयान के बाद इस मामले में बूंदी के चर्मेश शर्मा ने गुरुवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत की थी। जिस पर आयोग ने शुक्रवार को आयोग ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया।

नारी सम्मान की गरिमा के विरुद्ध बयान

मानवाधिकार आयोग में दर्ज शिकायत में बूंदी के कांग्रेस नेता चर्मेश शर्मा ने पहलगाम हमले के बाद भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी के विरुद्ध मध्य प्रदेश के सरकार के मंत्री विजय शाह द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी को भारतीय नारी सम्मान की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला और राष्ट्रीय एकता और अखंडता की विरुद्ध बताया गया है।

कड़ी कार्रवाई की मांग

शिकायत में मानव अधिकार आयोग से भारतीय सेना की सभी महिला अधिकारियों की नारी सम्मान की गरिमा सुनिश्चित करने के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी के विरुद्ध आपत्तिजनक बयान देने वाले मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है।

भारतीय सेना का सम्मान सर्वोपरि

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कर्नल सोफिया कुरैशी के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी पर मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाने वाले बूंदी के कांग्रेस नेता राजस्थान बीज निगम के पूर्व निदेशक चर्मेस शर्मा ने कहा कि भारतीय सेना का सम्मान सर्वोपरि है। किसी भी सैन्य अधिकारी का इस तरह से अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। शर्मा ने कहा कि यह और भी शर्मनाक है कि जिस व्यक्ति ने संविधान की शपथ लेकर एक राज्य सरकार के मंत्री का पद ग्रहण कर रखा है, उसके द्वारा ऐसी अपमानजनक टिप्पणी भारतीय सेना की महिला अधिकारी के विरुद्ध की गई है। शर्मा ने कहा कि प्रत्येक देशवासी को वर्तमान समय में भारतीय सेना का हर स्तर पर हर हौसला बढ़ाना चाहिए।

ETV Bharat

## कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी के मामले में मध्य प्रदेश के मंत्री शाह की बढ़ीं मुश्किलें, NHRC में केस दर्ज - MP MINISTER ROW

कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बूंदी के कांग्रेस नेता की शिकायत पर केस दर्ज किया है.

<https://www.etvbharat.com/hi/!bharat/mp-minister-vijay-shah-controversial-remark-on-colonel-sophia-qureshi-nhrc-filed-a-case-hindi-news-rjn25051604920>

By ETV Bharat Rajasthan Team | Published : May 16, 2025 at 7:05 PM IST

2 Min Read

बूंदी: भारतीय सेना की महिला सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने केस दर्ज कर लिया है. राजस्थान के बूंदी के कांग्रेस नेता चर्मेश शर्मा ने मंत्री शाह के खिलाफ आयोग से शिकायत की थी, जिसके बाद शुक्रवार को इस मामले में केस दर्ज किया गया है.

आयोग ने शुक्रवार को दर्ज किया केस : दरअसल, इस मामले में बूंदी के चर्मेश शर्मा ने गुरुवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत की थी, जिस पर शुक्रवार को आयोग ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के एक्शन में आने के बाद मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं.

नारी सम्मान की गरिमा के विरुद्ध मंत्री का बयान : मानवाधिकार आयोग में दर्ज शिकायत में बूंदी के कांग्रेस नेता चर्मेश शर्मा ने पहलगाम हमले के बाद भारत-पाकिस्तान तनाव के दौरान भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी के विरुद्ध मंत्री शाह की आपत्तिजनक टिप्पणी को भारतीय नारी सम्मान की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला व राष्ट्रीय एकता व अखंडता के खिलाफ बताया. शिकायत में मानवाधिकार आयोग से भारतीय सेना की सभी महिला अधिकारियों की नारी सम्मान की गरिमा सुनिश्चित करने के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक बयान देने वाले मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है.

भारतीय सेना का सम्मान सर्वोपरि - शर्मा : कांग्रेस नेता और राजस्थान बीज निगम के पूर्व निदेशक चर्मेश शर्मा ने कहा कि भारतीय सेना का सम्मान सर्वोपरि है और किसी भी सैन्य अधिकारी का इस तरह से अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. शर्मा ने कहा कि यह और भी शर्मनाक है कि जिस व्यक्ति ने संविधान की शपथ लेकर एक राज्य सरकार के मंत्री का पद ग्रहण कर रखा है, उसके द्वारा ऐसी अपमानजनक टिप्पणी भारतीय सेना की महिला अधिकारी पर की गई है. शर्मा ने कहा कि प्रत्येक देशवासी को वर्तमान समय में भारतीय सेना का हर स्तर पर हौसला बढ़ाना चाहिए.

City News Rajasthan

## कर्मल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी के मामले में मध्यप्रदेश के मंत्री शाह की मुश्किलें बढ़ी

<https://citynewsrajasthan.com/madhya-pradesh-minister-shah-troubles-increased-in-the-matter-of-commenting-on-colonel-sofia-qareshi>

3 घंटे ago in bundi, INDIA, RAJASTHAN

बूंदी के कांग्रेस नेता की शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दर्ज किया केस

बूंदी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर भारत की ओर से जवाबी कार्यवाही में शामिल महिला सैन्य अधिकारी कर्मल सोफिया कुरैशी पर मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केस दर्ज कर लिया है। आयोग ने बूंदी के कांग्रेस नेता राजस्थान बीज निगम के पूर्व निदेशक चर्मेश शर्मा की शिकायत पर शुक्रवार को केस दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। कर्मल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के एक्शन में आने के बाद मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं।

आयोग ने शुक्रवार को दर्ज किया केस

मंत्री विजय शाह के कर्मल सोफिया कुरैशी के विरुद्ध आपत्तिजनक बयान के बाद इस मामले में बूंदी के चर्मेश शर्मा ने गुरुवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत की थी। जिस पर आयोग ने शुक्रवार को आयोग ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया।

नारी सम्मान की गरिमा के विरुद्ध बयान

मानवाधिकार आयोग में दर्ज शिकायत में बूंदी के कांग्रेस नेता चर्मेश शर्मा ने पहलगाम हमले के बाद भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करने वाली कर्मल सोफिया कुरैशी के विरुद्ध मध्यप्रदेश के सरकार के मंत्री विजय शाह द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी को भारतीय नारी सम्मान की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला व राष्ट्रीय एकता व अखंडता की विरुद्ध बताया गया है।

कड़ी कार्यवाही की मांग

शिकायत में मानव अधिकार आयोग से भारतीय सेना की सभी महिला अधिकारियों की नारी सम्मान की गरिमा सुनिश्चित करने के साथ कर्मल सोफिया कुरैशी के विरुद्ध आपत्तिजनक बयान देने वाले मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की मांग की गयी है।

भारतीय सेना का सम्मान सर्विपरि – शर्मा

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कर्मल सोफिया कुरैशी के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी पर मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाने वाले बूंदी के कांग्रेस नेता राजस्थान बीज निगम के पूर्व निदेशक चर्मेश शर्मा ने कहा कि भारतीय सेना का सम्मान सर्विपरि है। और किसी भी सैन्य अधिकारी

का इस तरह से अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। शर्मा ने कहा कि यह और भी शर्मनाक है कि जिस व्यक्ति ने संविधान की शपथ लेकर एक राज्य सरकार के मंत्री का पद ग्रहण कर रखा है उसके द्वारा ऐसी अपमानजनक टिप्पणी भारतीय सेना की महिला अधिकारी के विरुद्ध की गयी है। शर्मा ने कहा कि प्रत्येक देशवासी को वर्तमान समय में भारतीय सेना का हर स्तर पर हर हौसला बढ़ाना चाहिये।

Patrika

## मंत्री विजय शाह के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, सरकार को जारी किया नोटिस

Minister Vijay Shah Case : मंत्री विजय शाह द्वारा सोफिया कुरैशी के खिलाफ दिए विवादित बयान को लेकर अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने सरकार को नोटिस जारी किया है।

<https://www.patrika.com/bhopal-news/national-human-rights-commission-took-cognizance-of-minister-vijay-shah-case-issued-notice-to-mp-government-19603036>

भोपाल•May 17, 2025 / 08:52 am•

Faiz

Minister Vijay Shah Case : भारतीय सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के मामले में मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री विजय शाह को लेकर एक तरफ जहां विपक्ष हमलावर होते हुए सरकार पर मंत्री को बचाने का आरोप लगा रही है तो वहीं दूसरी तरफ शाह की मुश्किले लगातार बढ़ती जा रही हैं। मंत्री विजय शाह द्वारा दिए बयान से जुड़े मामले में अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान ले लिया है। आयोग ने मामला दर्ज करते हुए मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है।

बता दें कि, राजस्थान के एक नेता चर्मेस शर्मा ने मामले की शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से की थी। इधर, मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 19 मई को सुनवाई होनी है। मंत्री विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया केविएट

हाईकोर्ट की ओर से अधिवक्ता जय ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में केविएट लगाया है। केविएट में कहा गया है कि, फैसले से पहले हाईकोर्ट का पक्ष भी सुना जाए। इंटरवीनर के रूप में सीनियर एडवोकेट कपिल सिंबल ने तुरंत सुनवाई की मांग रखी है।

Nagaland Post

## **NHRC writes to states, Union Territories on ending manual scavenging**

<https://nagalandpost.com/index.php/2025/05/17/nhrc-writes-to-states-union-territories-on-ending-manual-scavenging/>

May 17, 2025

The National Human Rights Commission (NHRC) has written to all states and Union Territories asking them to ensure “immediate implementation” of directives issued by the Supreme Court in a 2023 verdict, aimed at eradicating manual scavenging and hazardous sewer cleaning.

The rights panel has recommended a slew of measures to authorities, including the establishment of “robust monitoring systems to ensure real-time compliance and deterrence”, the rights panel said on Thursday.

The National Human Rights Commission (NHRC) has also asked the authorities to submit an action taken report within eight weeks, officials said.

In view of the continued practice of manual cleaning of hazardous waste, the NHRC, in a letter to all the chief secretaries and administrators of states and Union Territories, has “asked to ensure the immediate implementation of the 14 directives issued by the Supreme Court in its landmark 2023 judgment (Dr. Balram Singh v/s Union of India, 2023 INSC 950), aimed at eradicating the inhuman and caste-based practice of manual scavenging and hazardous sewer cleaning,” it said in a statement.

The commission has noted that the practice constitutes a “grave violation of human rights”, especially the right to life with dignity and equality before the law.

The NHRC has observed that despite the constitutional and legal safeguards, as well as a complete ban announced by the Supreme Court in January 2025 in six major cities — Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata, Bengaluru, and Hyderabad — manual cleaning of hazardous waste “continues to be reported in certain parts of the country”.

Therefore, the NHRC has recommended the immediate implementation of measures including wide dissemination of the prohibition of manual scavenging and relevant judicial directives among stakeholders, including local authorities, contractors, and the general public, it said.

Other measures include sensitisation programmes for government officials, sanitation workers, and communities on the legal, social, and human rights dimensions of manual scavenging; and regular follow-ups and review mechanisms to track progress, identify implementation gaps, and ensure accountability at all levels.

Pudhari News

## **National Human Rights Commission | हाताने धोकादायक कचरा सफाई त्वरित थांबवा: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग**

राष्ट्रीय: 'न्यायालयाच्या निर्देशांची तातडीने अंमलबजावणी करावी'

<https://pudhari.news/national/nhrc-orders-immediate-stop-to-manual-hazardous-waste-cleaning-human-rights-violation-nq81>

पुढारी वृत्तसेवा | Published on: 16 May 2025, 2:45 pm | Updated on: 16 May 2025, 2:45 pm

नवी दिल्ली : धोकादायक स्वरूपाच्या कचऱ्याच्या सफाईसाठी अजूनही हाताने सफाईची पद्धत वापरली जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या १४ निर्देशांची तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासकांना पत्राद्वारे दिल्या आहेत. आयोगाने संबंधित अधिकाऱ्यांना ८ आठवड्यांच्या आत कारवाईचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.

विष्ठा तसेच धोकादायक गटारांची हाताने सफाई मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणारी आणि जातीय भेदभावावर आधारित अमानुष प्रथा पूर्णपणे बंद करणे हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा उद्देश आहे. हाताने सफाईची पद्धत म्हणजे मानवी हक्कांचे विशेषतः सन्मानासह जगण्याच्या हक्काचे आणि कायद्यासमोर प्रत्येकजण समान असल्याच्या तत्वाचे गंभीर उल्लंघन असल्याची बाबही आयोगाने आपल्या पत्रात नमूद केली आहे.

धोकादायक कचऱ्याची हाताने सफाई करू नये यासाठी कायदेशीर संरक्षण असतानाही तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने २९ जानेवारी, २०२५ रोजी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बंगळूरु आणि हैदराबाद या ६ प्रमुख शहरांमध्ये अशा पद्धतीने सफाई करण्यास पूर्णपणे बंदी घातली असतानाही देशाच्या काही भागांमध्ये धोकादायक कचऱ्यासाठी हाताने सफाईची वृत्त येत असल्याचे निरीक्षणही आयोगाने आपल्या पत्रात नोंदवले आहे.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने सांगितलेल्या उपाययोजना

- स्थानिक अधिकारी, कंत्राटदार आणि सामान्य जनतेसह भागधारकांमध्ये हाताने मैला साफ करण्यावर बंदी आणि संबंधित न्यायालयीन निर्देशांचा व्यापक प्रचार करणे
- हाताने मैला साफ करण्याच्या कायदेशीर, सामाजिक आणि मानवी हक्कांच्या पैलूंबद्दल सरकारी अधिकारी, स्वच्छता कामगार आणि समुदायांसाठी जागरूकता कार्यक्रम राबवणे
- सुचनांची अंमलबजावणी आणि प्रतिबंध सुनिश्चित करण्यासाठी मजबूत देखरेख प्रणालींची स्थापना करणे
- कामाचा आढावा घेण्यासाठी, अंमलबजावणीतील तफावत ओळखण्यासाठी आणि सर्व स्तरांवर जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी नियमित पाठपुरावा आणि पुनरावलोकन यंत्रणा कामाला लावणे



News18

## **Murshidabad Violence Pre-Planned, Constitutes Organised Crime, Says Report Submitted To HC**

<https://www.news18.com/india/murshidabad-violence-pre-planned-constitutes-organised-crime-says-report-submitted-to-hc-ws-dl-9339109.html>

Reported By : Kamalika Sengupta | News18.com | Edited By: Pragati Ratti

Last Updated: May 16, 2025, 10:03 IST

The Calcutta High Court extended paramilitary deployment in Murshidabad due to unrest. The state must restore normalcy and compensate victims, the court said.

The Calcutta High Court has extended the deployment of paramilitary forces in Murshidabad "till further order" due to the recent unrest. The state has been instructed to take appropriate steps to restore normalcy. The court also expects the state to take adequate measures for compensation and rehabilitation for the victims of the violence that took place in April.

Murshidabad's Samserganj, Dhulian, and Suti have witnessed unrest and disturbances. The violence, vandalism, and mass panic were all pre-planned and constitute organised crime, according to a report submitted by a three-member committee appointed by the High Court.

The committee comprises one member each from the State Human Rights Commission, the National Human Rights Commission, and the State Legal Services Authority (SLST).

Justice Soumen Sen's division bench of the High Court has directed the assessment of damages caused by the Murshidabad violence. A court-empaneled valuer has been assigned to determine the actual extent of damage. The report is to be submitted by July 30.

Justices Soumen Sen and Raja Basu Chowdhury of the Division Bench have scheduled the next hearing for May 30.

A report from the three-member committee appointed by the High Court was submitted to the Division Bench led by Justice Soumen Sen. Based on complaints received, 142 new cases have been filed. The report highlights that homes have been vandalised and destroyed, with incidents of looting.

Many residents are living in fear and are traumatised by the incidents, the reports says. All affected individuals have demanded a permanent BSF (Border Security Force) camp. A list of victims and affected persons has been prepared. The committee has recommended actions for rehabilitation and compensation, as well as steps to restore confidence and morale among the people. Adequate police protection has also been advised.

Regarding the Murshidabad unrest, the state government has reported that over 1,100 social media accounts have been blocked. Rehabilitation has been provided to 82 families who had fled due to the violence, and 360 people have been brought back to their homes. In the Jangipur Police District alone, 348 arrests have been made, with arrests still ongoing. Additionally, 92 FIRs have been registered.

The Hindu

## **Murshidabad violence victims anxious about safety, State must ensure protection: Calcutta HC**

The court notes that the committee report points to vandalism and massacre as 'premeditated and an organised crime'; the court added that the victims' demand for a permanent camp of Central forces shall be considered

<https://www.thehindu.com/news/national/west-bengal/murshidabad-violence-victims-anxious-about-safety-state-must-ensure-protection-calcutta-hc/article69584113.ece>

Published - May 16, 2025 10:38 pm IST - KOLKATA

Moyurie Som

The Calcutta High Court observed that victims of Murshidabad violence are anxious about their safety in the violence-affected areas, and said that the State must ensure their rehabilitation, safety and protection.

"They should be restored to their original place after restoring confidence in the system. In the interregnum, the State must ensure proper shelter and accommodation to the victim. Upon restoration and rehabilitation, the State must ensure their safety and security. It should be the duty of the administration to ensure peace, harmony and protection of the property and lives of the victims," a Division Bench of Justices Soumen Sen and Raja Basu Chowdhury stated on Thursday (May 15).

Violence had erupted in Murshidabad's Samsherganj police station area on April 11 and April 12 following a protest against the passage of the Waqf (Amendment) Act, 2025. In the extended areas of Dhulian municipality and Tinpakuria gram panchayat, several houses and shops were torched and vandalised on these two days.

On April 12, a father and son were killed in Samsherganj's Jafrabad during the violence, and another person died in police firing in Suti police station area.

A three-member committee was formed in April on the directions of the Calcutta High Court to submit a report for the restoration of normalcy and rehabilitation of the victims. It has one member each from the National Human Rights Commission, West Bengal State Human Rights Commission and the State Legal Services Authority.

'Premeditated vandalism and massacre'

The court in its May 15 order stated, "It is revealed from the report of the committee that the vandalism and massacre are premeditated and appears to be an organized crime."

The report and video footage submitted by the committee also noted extensive damage to property and livelihood at Betbona village, Palpara and Ghoshpara in Samsherganj area. It was also observed from the committee's report that several homes were

vandalised, people's source of livelihood was taken away, and movables of every possible kind "pilfered and looted with impunity".

"The victims appear to be in a sorry state of affairs... It appears from the report that presently the victims are not acutely dissatisfied with the relief measures but they are anxious about their meaningful existence in view of their sufferings," the Calcutta High Court observed.

The court pointed out that the State shall take note of the anxiety expressed by the victims and take appropriate measures in this regard.

'Shall consider permanent BSF camp'

Meanwhile, the Calcutta High Court highlighted the committee's observations on the role of the police and said it "shall consider" the victims' demand for a permanent camp of the Border Security Forces (BSF).

"The report submitted by the committee has posed a serious question as to the efficacy of the investigation considering the huge number of cases resulted from the violence... the committee was of the view that there may be a reasonable negative view on the police's performance having regard to the facts came to the notice of the team... Shock and trauma were writ large on the faces of the sufferers and the common grievance was lack of timely police assistance," the court noted.

As of May 16, the West Bengal Police have made 353 arrests in connection with the mob violence, and a total of 13 arrests in connection with the murder of father-son duo Hargobind Das and Chandan Das outside their home in Samsherganj's Jafrabad on April 12.

It is also worth noting that the bereaved Das family, which rejected the State's compensation, had petitioned the Calcutta High Court for an inquiry by the Central Bureau of Investigation (CBI).

The petition was earlier released by the Single Bench of Justice Tirthankar Ghosh since the aforementioned Division Bench was already hearing matters pertaining to the Murshidabad matter. However, on May 15, the Division Bench of Justices Soumen Sen and Raja Basu Chowdhury also released the matter for it to be placed before the Chief Justice.

State's compensation

The State, in its affidavit to the court, stated that as many as 1,093 social media accounts have been blocked since April 11.

According to counsel Kalyan Bandopadhyay, who appeared on behalf of the State, the government also formulated a rehabilitation project and sanctioned a sum of ₹3,69,60,000 to rehabilitate almost 283 families identified till now, for reconstruction of their houses under 'Banglar Bari Scheme'.

Mr. Bandopadhyay also drew the court's attention to the fact that Chief Minister Mamata Banerjee, during her recent visit to the area, handed over cheques worth ₹1.2 lakh each to 283 households, along with 40 sewing machines and 40 riot-affected victims.

After the Chief Minister's visit, a large police camp was also set up in the riot-hit area of Samsherganj.

GEO News

## **Global calls intensify to hold Modi accountable for human rights abuses**

Petition was launched on the same day Pakistan urged the UNSC to take notice of IIOJK's dire situation

<https://www.geo.tv/latest/604812-call-for-making-modi-accountable-for-human-rights-abuse>

By Nasim Haider |May 16, 2025

A petition has been launched in the United States to bring Indian Prime Minister Narendra Modi and two of his close associates to justice for their "involvement in human rights abuses in India".

"We, concerned global citizens, urgently call for accountability and international action against Indian Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, and National Security Advisor Ajit Doval for their active role in enabling and escalating grave human rights violations across India," reads the document.

The petition was moved by American-Pakistanis, and it has listed "state-sponsored violence against peaceful demonstrators, systematic targeting of religious and ethnic minorities, censorship and criminalisation of dissenting voices, misuse of authoritarian laws like UAPA and sedition to crush democratic freedoms, and neglect of public safety" as some of the main human rights abuses by the Modi government.

The petitioners have urged the United Nations Human Rights Council (UNHRC), global human rights organisations, and democratic governments around the world to launch independent investigations into rights abuses committed under the current Indian regime, and to apply diplomatic and economic pressure to end state repression and restore democratic norms in India.

The timing of this petition is critical, as it was launched on the same day Pakistan urged the United Nations Security Council (UNSC) to take notice of the dire situation in Indian Illegally Occupied Jammu and Kashmir (IIOJK).

In a policy statement during the Security Council briefing on the implementation of Resolution 2474, Ambassador Asim Iftikhar Ahmad, Permanent Representative of Pakistan to the UN, highlighted the plight of missing Kashmiris at the hands of Indian occupation forces.

Asim Iftikhar, representing Pakistan, said that India had used the pretext of the recent terrorist incident to round up more than 2,000 people to further suppress Kashmiris' struggle for their legitimate right to self-determination.

"Missing persons are not just numbers. They are fathers who never returned home, mothers separated from their children, young boys who disappeared in the dead of night, and daughters whose fates are sealed in silence. Their absence is a wound that never

heals, leaving families trapped in an endless cycle of hope and despair," he said, describing the despair of the affected Kashmiris.

Asim Iftikhar further said, "From the investigations held so far, it has been revealed that these victims are first disappeared by Indian occupation forces and then tortured to death or summarily executed."

He reminded members that the Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), in its two reports of 2018 and 2019 on Kashmir, had recommended to "ensure independent, impartial and credible investigations into all unmarked graves" in IIOJK.

The permanent representative demanded that every missing person be accounted for, family connections be restored, and the fundamental rights of those lost in the chaos of conflict be upheld.

He stressed that the issue of missing persons is a symptom of unresolved conflicts, which need to be addressed.

International organisations have also questioned the human rights record of the Modi government.

According to Human Rights Watch, "Indian authorities continued to restrict free expression, peaceful assembly, and other rights in Jammu and Kashmir. Reports of extrajudicial killing by security forces continued throughout the year."

Human Rights Watch (HRW) maintained that the Modi regime has persisted with its policies of discriminating against and stigmatising religious and other minorities, which has led to increasing incidents of communal violence in many parts of India.

"Allegations of torture and extrajudicial killings persisted, with the **National Human Rights Commission** registering 126 deaths in police custody, 1,673 deaths in judicial custody, and 55 alleged extrajudicial killings in the first nine months of 2023," said the HRW in a statement.

And, in a recent report, Amnesty International pointed out: "National financial and investigation agencies were weaponised against civil society, human rights defenders, activists, journalists and critics, further shrinking civic space.

Authorities continued to unlawfully demolish properties belonging to religious minorities as a means of meting out extrajudicial punishment."

Experts say it is strange that despite all these accusations by HRW and AI, hardly any action is taken against the repressive Indian regime.

The Wire

## **Seshachalam Tragedy: A Decade of Silence and Desperate Call for Justice**

<https://thewire.in/rights/seshachalam-tragedy-a-decade-of-silence-and-desperate-call-for-justice>

Vanaja Jaspine and Edgar Kaiser 7 hours ago 5 min read

On April 7, 2015, the Seshachalam forest in Chittoor district, Andhra Pradesh, became the backdrop for one of the darkest chapters in India's fight for human rights.

On the 10th anniversary of the Seshachalam tragedy, this year, families of the victims, their neighbours, and civil society actors gathered to commemorate the demise of those who succumbed to state violence in 2015. This year, the solemn gathering took place at one of the victims' homes in Polur, Thiruvannamalai district in Tamil Nadu, where victim families from Thiruvannamalai, Dharmapuri and Salem districts came together to mourn. They paid homage to their husbands, sons and brothers, sharing their pain and anguish while vehemently placing forward their demand for justice.

The loss remains fresh, and the victims' families continue to feel hopeless as they seek recognition for their suffering and demand action from both the state governments and the National Human Rights Commission (NHRC). These men, who were the sole breadwinners, ventured out in search of a livelihood, oblivious of the life-changing tragedy that was waiting for them.

### The 2015 tragedy in Seshachalam forest

On April 7, 2015, the Seshachalam forest in Chittoor district, Andhra Pradesh, became the backdrop for one of the darkest chapters in India's fight for human rights. Twenty individuals from Tamil Nadu were taken by the Andhra Pradesh Red Sanders Anti-Smuggling Task Force (STF) from several districts close to Andhra Pradesh border and were shot to death, backed by the usual narrative of a police encounter.

Nine alleged red sandalwood smugglers were killed in one place and 11 in a second clash a kilometre away in Chittoor. These men had left their homes with the hope of earning a livelihood, only to be caught in a politically charged conflict over the precious red sandalwood. The victims were captured, tortured and murdered, and their bodies discarded in the dense forest, as the authorities sought to bury the truth along with them.

### Aftermath of the encounter killing: a tarnished justice process

The NHRC took suo motu cognisance of the incident the same day and issued notices to the Andhra Pradesh chief secretary and the director-general of police of Andhra Pradesh to submit a detailed report. In May 2015, the NHRC directed the Andhra Pradesh government to pay Rs 5 lakh as interim relief and ordered the government to provide financial assistance under the SC/ST (POA) Rules to the families of each of the 20 persons killed by the STF personnel within eight weeks.



In June 2015, the Andhra Pradesh chief secretary filed a petition before the Andhra Pradesh high court challenging the direction of the NHRC. The high court ordered an interim stay of the NHRC's order.

Ten years after the incident, the interim stay had not been vacated, and the proceedings before the high court were still pending. Later, NHRC never materialised its efforts to effectively intervene in the court proceedings to lift the interim stay, as a result of which, the case now remains unresolved.

In an effort to provide relief, the Tamil Nadu state government provided compensation of Rs 3 lakh and jobs to each of the 20 woodcutters' families. However, the low-paying jobs offered by the government, with wages ranging from Rs 3,000 to Rs 4,000 per month, make it extremely challenging for them to meet their basic needs. Many families, now headed by single mothers, struggle daily to make ends meet. Children are deprived of education, and poverty continues to bind them in an unbreakable cycle. Despite the government's small gesture, the families remain trapped in financial hardship and emotional pain.

The tragedy remains a haunting reminder of a system that utterly failed to protect the lives of the innocent and even to provide justice after the incident.

Ten years on, the families of these victims continue to seek justice, but both the state governments have remained largely silent.

The surging encounters in different parts of India including Sambhal, Tamil Nadu and Bastar further highlights the need for reform in law enforcement. These incidents underscore the importance of proper training, transparency, and oversight in police operations as recommended by the Administrative Reforms Commission in 2007 and the National Police Commission in 1980.

Police funds should be allocated to strengthen law enforcement agencies, ensuring that they can handle sensitive situations without resorting to excessive force. Additionally, independent bodies must be established to investigate unlawful police actions, such as the Seshachalam encounter, and hold accountable those behind it.

Hope amidst despair

As years passed, the Seshachalam tragedy faded from the public and state consciousness, as the families of the victims were abandoned to mourn in silence. No charges were brought against the perpetrators, and the wounds of the families remain open. Recently, the Joint Action Against Custodial Torture (JAACT) from Tamil Nadu has appealed to the National Human Rights Commission to vacate the 10 year long stay before the high court and provide justice to the innocent victim families. Though the struggle for justice may seem endless, the call for justice and act of remembrance brings us closer to healing.

What is very important here is that every year when the victims come together on April 7, they hope that something better will happen in their lives to bring justice to the martyrs.

The Seshachalam tragedy has turned into a reminder of relentless hope for justice, collective awakening, for the determination of the voiceless and a stark reminder that even the smallest light can pierce the darkest night. The NHRC, which was very swift in taking suo moto cognisance, ordered compensation and also listed this case in their important interventions, must ensure that “Justice must not only be done, but must also be seen to be done”.

Vanaja Jaspine and Edgar Kaiser are human rights lawyers at People’s Watch.

Dainik Bhaskar

## वक्फ बोर्ड मामला: मानव अधिकार आयोग ने कलेक्टर से चार सप्ताह में मांगी रिपोर्ट

<https://www.bhaskar.com/local/mp/raisen/news/wakf-board-case-human-rights-commission-seeks-report-from-collector-in-four-weeks-135034831.html>

रायसेन 20 घंटे पहले

रायसेन। माखनी गांव की भूमि पर वक्फ बोर्ड के कब्जे के प्रयास को लेकर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने कलेक्टर और एसपी से मामले की पूरी जानकारी और कार्रवाई रिपोर्ट चार सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध दस्तावेजों के किसी को भी उसकी संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता। शिकायतकर्ता अनिरुद्ध केशरे ने आयोग को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि वक्फ बोर्ड द्वारा ग्राम माखनी की भूमि पर अवैध कब्जा करने और ग्रामीणों को बेदखल करने की कोशिश की जा रही है।

शिकायत के अनुसार, वक्फ बोर्ड ने खसरा नंबर 178 और 179 रकबा 1.413 हेक्टेयर पर दावा जताते हुए ग्रामीणों को नोटिस भेजा था, जबकि उक्त भूमि पर उनका वर्षों से कब्जा है और वे वहीं निवासरत हैं। शिकायत में यह भी कहा गया कि यह कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन जीने का अधिकार) और अनुच्छेद 300-ए (संपत्ति का अधिकार) का उल्लंघन है। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय का हवाला देते हुए कहा है कि जब तक कोई स्थायी धार्मिक संरचना या समर्पण का प्रमाण न हो, तब तक केवल दीवार या चबूतरे के आधार पर किसी भूमि को धार्मिक घोषित नहीं किया जा सकता।

Sudarshan News

## लव जिहाद के खिलाफ सकल हिन्दू समाज की हुंकार, रैली में NIA जांच की मांग की

मध्य प्रदेश में बढ़ते लव जिहाद के मामलों को लेकर गुना में सकल हिन्दू समाज ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया।

<https://www.sudarshannews.in/news-detail.aspx?id=127264>

Deepika Gupta | May 16 2025 3:28PM

मध्य प्रदेश के गुना जिले में 'लव जिहाद' के मामलों को लेकर शुक्रवार को सकल हिन्दू समाज के बैनर तले सैकड़ों नागरिकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हनुमान चौराहे से कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने 'लव जिहाद' के कथित मामलों की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से जांच कराने की मांग की।

रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों ने लव जिहाद के खिलाफ नारेबाजी की और आरोपी व्यक्तियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। एडवोकेट आशा किरण कौर ने जानकारी देते हुए कहा कि यह समस्या अब मात्र व्यक्तिगत नहीं रही, बल्कि यह हिन्दू समाज की बेटियों के खिलाफ एक सुनियोजित और संगठित षड्यंत्र बन चुकी है।

उन्होंने कहा, "विधर्मी युवक अपनी पहचान छुपाकर मासूम नाबालिग बालिकाओं और युवतियों को प्रेमजाल में फंसा रहे हैं। उनके साथ शारीरिक शोषण और धर्मांतरण किया जा रहा है। यह केवल कुछ जिलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राज्य के अधिकांश जिलों में यह संगठित नेटवर्क बन चुका है, जिसकी जड़ें अंतरराज्यीय और संभवतः अंतरराष्ट्रीय स्तर तक फैली हो सकती हैं।"

प्रदर्शनकारियों ने यह कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा इस मुद्दे पर संज्ञान लिया जाना इस बात का प्रमाण है कि मामला अत्यंत गंभीर और संवेदनशील है। ऐसे में NIA ही एकमात्र सक्षम एजेंसी है जो इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश कर सकती है और अपराधियों को न्याय के कठघरे तक पहुंचा सकती है।

ज्ञापन में मांग की गई कि बेटियों की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए इस पूरे प्रकरण को NIA को सौंपा जाए और दोषियों पर राष्ट्रद्रोह के तहत कठोर कार्रवाई की जाए। प्रदर्शन शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, लेकिन हिन्दू समाज की ओर से दी गई चेतावनी स्पष्ट थी – अगर बेटियों के सम्मान और सुरक्षा से समझौता किया गया, तो आंदोलन और तेज़ होगा।